[Shrimati Indira Gandhi]

the proof of the appreciation is: why do people attach so much importance to what we think or what we say or what we do.

SHRI M. R. MASANI: Do they?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: They do. It may disappoint Mr. Masani and Mr. Masani has been saying this practically from the first day even when some other hon. Members thought that India was the leader of the un-developed world. Even at that time he thought that India's voice was not heard. India's voice is heard and the ample proof of it was given in the last session of the United Nations.

I want to apologise to hon. Members for not being here tomorrow and I hope that any new points that they make will be dealt with suitably.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Are you going to allow the South African Delegation to come to Delhi for the UNCTAD Conference?

SHRI J. B. KRIPALANI: The Prime Minister began in Hindi, then when she got excited, like every one, she slipped into English.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I believe in bi-lingualism.

SHRI N. DANDEKER (Jamnagar) May I ask the Prime Minister whether she will assure the House that this poor Russian will not be handed over to Russia?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I told hon. Members that the matter is being looked into and I do not think it will be right for me to give an answer before we have got all the facts.

The hon. Member has asked about the UNCTAD. As he knows, this United Nations Conference is being held on the terms and conditions of the United Nations.

There was one other point which Mr. Indrajit Gupta has raised. It was about NLF. Here again I think our point is very clear that we have always said that they should be a party to any talks on settlement, to any settlement that will be held. We have not at all ignored them.

SHRI NATH PAI *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: This debate will continue tomorrow.

SHRI NATH PAI: I do not want to ask any question. We have no illusions of getting any reply to our questions. Just I want to know as to who will be replying to the debate tomorrow when it is resumed.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: That you will know.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That will be known tomorrow.

15.44 HRS.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTEENTH REPORT

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 18वें प्रतिवेदन से, जो 20 दिसम्बर, 1967 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House agrees with the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th December, 1967."

The motion was adopted.

15.44½ HRS.

RESOLUTION *RE*: IMPLEMENTATION OF SAHIBINADI SCHEME—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now proceed with the further discussion of the Resolution moved by Shri Gajraj Singh Rao on the 8th December, 1967 regarding the Implementation of Sahibinadi scheme.

Shri Gajraj Singh to resume his speech.

श्री गजराज सिंह राव : (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने साहबी नदी के बारे में प्रस्ताव पेश किया तो कुछ साहबान ने कहा कि यह छोटी सी बात आप इतनी

बड़ी पार्लियामेन्ट में आये हैं, गर्जेकि लोगों ने अपने-अपने नुक्ते निगाह से उसकी नुक्ता-चीनी की । लेकिन इसकी बैकग्राउण्ड में जो चीज है, वह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं । हिन्दुस्तान की हायस्ट अथारिटीज और बड़े-बड़े इन्जनियरों की तरफ़ से उस गरीब इलाके को बचाने के लिये जो 264 सफे की रिपोर्ट लिखी गई, उसमें जगह-जगह पर इस साहबी नदी का जिक्र है । इस रिपोर्ठ में गवर्नमेन्ट आफ़ इण्डया भी शामिल थी, पंजाब गवर्नमेन्ट भी शामिल थी ।

15.45 Hrs.

[Shri Bal Raj Madhok *in the Chair*.]

जनाब, नजफ़गढ़ का इलाका, जिसके 50–60 गांव हर साल साहबी नदी की बाढ़ में डूबते हैं, पानी वहां पर जमा हो जाता है और वहां बड़ी खराब हालत हो जाती है । 20 साल हुए करोड़ों रुपये की मीटर गेज की छोटी लाइन इस नदी की बाढ़ में टूटी और नतीजा यह हुआ कि रेलवे को 12–15 पुल उस नदी पर बनाने पड़े । मैं यह महसूस करता हूं कि अगर उसका 100वां हिस्सा भी इस स्कीम पर लगा दिया जाता तो यह नुकसान न होता । बल्कि इससे यह फायदा होता कि—आम के आम और गुठलियों के दाम—उस गरीब इलाके को जिसको गदर में हिस्सा लेने की सजा मिली थी, जिसको सन 1857 की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की सजा मिली था—उनको मीठा पानी मिल जाता —आज वहां मीलों तक खारा पानी है—और उस इलाके पर जो तबाही आती है, उससे बच सकते थे । लेकिन हमारे अफ-सरान उसको कभी किसी बहाने से टलवाते रहे और कभी किसी बहाने से—कभी कहते कि महाराज अलवर की शिकारगाह है, इस लिये वहां पर रिजरवायर—बांध नहीं बन सकता, कभी कहते कि वह बाबल का इलाका है, इस लिये यह चीज नहीं हो सकती, लेकिन रिवाड़ी स्टेशन पर पानी कहां से आता है—9 मील दूर साहबी के बीच वाटर वर्क्स लगा रखा है, वहां से पानी आता है मैं यह कहता हूं कि अगर यह बांध बना दिया जाय तो सिर्फ रिवाड़ी स्टेशन ही नहीं, बल्कि सारे इलाके को मीठा पानी मिल जाय, लोगों की दिक्कतें दूर हो जायें ।

एक दिक्कत यह बताई जाती है, कि साहब, यह हरियाणा का हिस्सा है और यह दिल्ली का हिस्सा है—बात कैसे बने । मैं कहता हूं कि अब तो हरियाणा भी सेन्ट्रल गर्वमेंट के अण्डर आ गया है, अब तो यह कानूनी दिक्कत भी जाती रही । इस स्कीम से हमारा असल मकसद यह है कि हमारी रेलवे लाइन बार-बार टूटने से बचे, सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का नुकसान न हो, दिल्ली का एरिया बाढ़ से बचे, उस पानी का इस्तेमाल इन तमाम इलाकों में आबपाशी के लिये किया जा सके और लोगों को मीठा पानी पीने के लिये मिल जाये । मैं आपको अर्ज करूं कि इस बात का रिकार्ड है कि झज्जर और रिवाड़ी के इलाके में 50 से 100 मौतें इस बात पर हुई हैं कि सवेरे कौन अपना घड़ा पानी का भरे । वहां के गंदे जोहड़ों और कूओं पर औरतें पानी के लिये आपस में लड़ती हैं ।

मैं आपको अर्ज करूं कि यह वह इलाका है जिसने 1857 में आजादी की लड़ाई का झण्डा बुलन्द किया था । राव कृष्ण गोपाल के साथ अंग्रेजों की लड़ाई नारनौल के पास हुई और उसकी सजा अंग्रेजों ने यह दी कि उस इलाके को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया । लेकिन अब यह सजा उनको क्यों दी जा रही है । बेइमान से बेइमान सूद खोर का ब्याज भी 6 फीसदी होता है, अब तो 110 साल हो गये, इस सजा से उनको अब माफ़ कर देना चाहिये । मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े इन्जीनियर, जिन से आज अम-रीका सलाह करता है, जिन से जर्मनी सलाह करता है—रायबहादुर कंवर सैन, डा० पाल, जिनको आज दूसरे मुल्कों में सलाह के लिये बुलाया जाता है, उन्होंने इस

[श्री गजराज सिंह राव]

डाक्यूमेन्ट में कहा है कि यही एक स्कीम है जिसके जरिये दिल्ली के इलाके को बचाया जा सकता है । इस रिपोर्ट को आप पढ़ें--इसमें जगह-जगह पर यह चीज़ मौजूद है । पानी के मसले को सेंटर के लेवल पर और स्टेट्स के लेवल पर लिया गया लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला है । पीने के पानी तक की मुश्किल हो रही है । इस एरिया ने क्या जुल्म किया है ? अगर जुल्म किया भी था कभी किसी जमाने में तो क्या आज भी उसको पीने तक को पानी न मिले, वे लोग तरसते रहें ? इससे जो मैं कह रहा हूं पानी की सहूलियत भी पैदा हो जाती है ।

इसको इम्प्लेमेंट क्यों नहीं किया गया ? मैं बता चुका हूं कि पहले तो अलवर के राजा ने आब्जैक्ट किया था कि मेरी शिकारगाह खराब हो जाएगी, इसलिये नहीं होना चाहिये । फिर नाभे वाले ने कहा कि मैं रेल को पानी देता हूं और मुझे इतने हज़ार रुपये रेलवे देती है । इससे मेरा यह काम बिगड़ जाएगा अगर सब जगह पानी आ गया तो ।

एक माननीय सदस्य : राजे काम खराब कर रहे हैं ।

श्री गजराज सिंह राव : ठगों का गिरोह है ।

साढ़े बारह करोड़ की स्कीम बनाई गई कि नजफगढ़ से ले कर जमुना में पानी डाल दिया जाए । उसमें ठेकेदार भी कमाई करें और दूसरे भी कमाई करें । किसी का मकान बीच में आता है तो वह कहेगा सेन साहब इसका पांच हज़ार या दस हज़ार दे दो । इस तरह से पचास करोड़ चला जायगा और स्कीम तो चलेगी नहीं । ऐसी ऐसी स्कीमें पेश की जा रही हैं ।

मैं सब डैपूमेंट्स पेश नहीं करता हूं । आखिरी जो रिकोमेंडेशन है पेज 87 पर साहिबी नदी स्कीम की उसको मैं पढ़ देता हूं । अशोक मेहता डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन में जब थे तो वह भी इस कमेटी के सामने पेश हुए थे सैन्ट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी थे, मैं पारलियामेंट की तरफ से नुमाइंदा था, पंजाब के नुमाइंदे भी थे, सब जगह के नुमाइंदे उसमें थे । इसमें यह लिखा हुआ है :—

"A large area in tehsil Gurgaon and tehsil Jhajjar of district Rohtak are flooded on account of the waters coming in the Sahibi Nadi from the Rajasthan side. Bunds for flood protection have to be constructed on these nadis in the upper reaches by the Rajasthan Government and by Punjab in district Gurgaon. The Committee is of the view that the Centre should be approached for the early execution of these projects. Since there is considerable damage to railway lines and to crops and property in the Delhi territory and as both Rajasthan and the Punjab Governments are involved, these schemes should be 'Centrally-sponsored' and Punjab's share should be provided by the Central Government".

This is the recommendation on the Sahibi Scheme.

अगर आप यह कहें कि वे तो ऐसे वैसे आदमी थे और आप बड़े बड़े ऐक्सपर्ट हैं इस वास्ते इसको आपने नामंज़ूर कर दिया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । इसका मतलब तो यही है जो गुलाम इलाका रहा है, जो दबा हुआ इलाका रहा है वह आगे क्यों आए । तब इसका नतीजा सही निकलता है कि इस इलाके की सज़ा बदस्तूर कायम रहनी चाहिये । यह रीज़निंग तो आप दे सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं जो राजे महाराजे हैं वे गरीब लोगों का खून चूसते रहे । अगर यह बात नहीं है तो कोई दूसरी दलील आप नहीं दे सकते हैं । मैं नहीं समझता हूं कि कुछ ज्यादा कहने की मेरे लिए जरूरत है । मैं समझता हूं कि तमाम माननीय सदस्य चाहे वे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों इस बात से मुतफिक होंगे । यह

ह्यूमैनिटी का काम है, उन लोगों को जो सजा मिली हुई है उस सजा को माफ करने का काम है। मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे।

MR. CHAIRMAN : Resolution moved :

"This House is of opinion that, with a view to provide irrigation and drinking water facilities to backward areas of Haryana (Rewari and Jhajjar tehsils) and Alwar District of Rajasthan and in order to avoid constant flooding of Najafgarh area of Delhi State and damage to Railway line (metre gauge), implementation of Sahibinadi scheme (raising Bunds etc.) is of urgent necessity and importance and urges upon the Government its speedy completion and effective utilisation".

There is an amendment tabled by Shri Yashpal Singh. He is absent.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री (बागपत) : जैसा कि श्री गजराज सिंह जी ने बताया है कि इस इलाके में झज्जर आता है, गुड़गांव का बहुत सा इलाका आता है और यहां के लोग नौ महीने पानी के लिए तरसते रहते हैं और ढोर भी पीने के पानी के लिये तरसते रहते हैं। कुछ महीनों के लिये बाढ़ का पानी आता है और वह सारी की सारी जमीनों को और सारे इलाके को डुबा देता है। निर्माण और विकास के युग में आवश्यकता इस बात की है कि उनको खेती के लिए पानी मिले, सिंचाई के लिए पानी मिले, और साथ-साथ पीने के लिये पानी मिले। यह पिछड़ा हुआ इलाका है और इस इलाके की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि पानी को इस तरह से नियंत्रित किया जाय कि जो पानी विनाश करता है, प्रलय लीला मचाता है उसके स्थान पर वह कुछ निर्माण के, उत्पादन के, उन्नति के तथा विकास के काम में आ सके। यह भी निश्चित है कि जितना नुकसान होता है वह जनता का और सरकार का होता है। मैं समझता हूं कि जितना नुकसान इसके कारण से एक साल में होता है उससे कम रुपये में इस सारी योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है। सरकार को जो करोड़ों रुपये का फसलों का नुकसान होता है, पशुओं का नुकसान होता है या दूसरी प्रकार की क्षतियां होती हैं उसकी हो सकता है चिन्ता न हो लेकिन सरकार को अपनी जो उसकी रेलें हैं उनको तथा दूसरी प्रकार का जो बहुत सा नुकसान होता है, उसका तो ध्यान रखना चाहिये, उसको तो होने से बचाना चाहिये।

झज्जर का इलाका जहां से साहिबी नदी राजस्थान से हो कर पहले झील बनाती है फिर नजफगढ़ के पास जहां पहले से ही झील बनी है मिल कर उस पानी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। आपको दिल्ली की याद होगी कि इस पानी को लेकर दिल्ली और पंजाब की सरकार में जब हरियाणा नहीं बना था एक लड़ाई सी चली थी जैसे कि दो देशों में लड़ाई होती है। एक दफा तो दिल्ली की पुलिस ने पंजाब के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था और एक दफा पंजाब की पुलिस ने दिल्ली के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। यह जो पानी है यह इधर उधर मारा-मारा फिरता है और दोनों सरकारों को आपस में लड़ाता रहता है। लेकिन पानी को ठीक दिशा देने में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

हरियाणा की क्षति को देखते हुए इसको मैं समझता हूं टाप प्रायोरिटी दी जानी चाहिये, इसको एक तात्कालिक आवश्यकता समझा जाए और तुरन्त कोई पग उठाये जायें। मैं चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय उत्तर दें तो कोई निश्चित बात बतायें और ऐसा न बतायें जैसा वे आम तौर पर बताया करते हैं, गोलमोल शब्दों में न बतायें जिन से पता ही न लग सके कि क्या वह करके जा रहे हैं। दिल्ली तो यूनियन टैरिटरी है

[श्री रघुबीर सिंह शास्त्री]

और हरियाणा भी अब एक तरह से यूनियन टैरिटरी है । इसलिए अब तो आपके पास कोई बहाना हो ही नहीं सकता है और आप कह ही नहीं सकते हैं कि आप यह करेंगे, वह करेंगे । आप ही अब सब कुछ करने वाले हैं। वहां लोगों की तकलीफ को आप समझें जल्दी से जल्दी ऐसी कारंवाई करें जिससे आगे से यह विपत्ति न आए और पहले ही जनता के कष्टों का निवारण हो जाए और यह पानी नियंत्रित हो कर लोगों को बरबाद करने के बजाए निर्माण के, सिंचाई के काम में आए ।

श्री भोला नाथ (अलवर) : यही राजस्थान का सब से बड़ा मसला है । राजस्थान में अलवर से हो कर और उसको काट कर यह नदी आती है जिसका प्रस्ताव में जिक्र है । राजस्थान सरकार ने कई बार यह योजना बनाई है, साहिबी नदी को बांधने की योजना बनाई है और उसने पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना में भी अस्सी-अस्सी लाख रुपया इसको बांधने के लिये रखा था । लेकिन दुख की बात है कि यह अस्सी लाख की योजना क्योंकि केन्द्र से कोई सहायता न मिली इसलिए अलवर जिले में साहिबी नदी को बांधने की योजना अभी तक कामयाब नहीं हुई । नतीजा यह है कि हर साल जब बारिश का समय आता है तो दिल्ली में भी यह नदी कोलाहल मचाती है और अलवर, भरतपुर में भी परेशानी पैदा करती है । इसके कारण उत्तर प्रदेश वाले भी चिल्लाते हैं । मेरा निवेदन यह है कि अब इस योजना को ज्यादा दिन तक पेंडिंग में न रखा जाए और तुरन्त इस पर अमल किया जाए । कंवर सेन जी राजस्थान में भी इंजीनियर रहे हैं और अलवर और भरतपुर में भी रहे हैं । वह खूब अच्छी तरह से साहिबी नदी की बात को जानते हैं, इसके पानी के उपयोग की बात को भी जानते हैं । धन की कमी की वजह से यह योजना हमारे इलाके में अभी तक अमल में नहीं आई है और साहिबी नदी को बांधा नहीं गया है । इस साहिबी नदी की बाढ़ की वजह से जो अलवर में हो कर नैशनल हाइवे नम्बर आठ जाता है, उसका भी डाइवर्शन कर दिया गया । वह अब सीधा रेवाड़ी से पास हो कर जयपुर को जाने लगा है, जिसका नतीजा यह है कि उसको बनाने में करोड़ों रुपये खर्च हो गए, लेकिन अलवर में साहबी नदी को बांधने के लिए तीन योजनाओं में अस्सी लाख रुपये खर्च नहीं किये गये। यह तो वैस्टेज है । आप देखें कि जो नेशनल हाईवे अलवर हो कर जाता है बरसात के दिनों में वह खराब हो जाता है । अगर आप गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जायें, तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत बड़े हिस्से में पानी भरा हुआ है और कोई खेती नहीं हो पाती है । वह पानी बिल्कुल बेकार जा रहा है । इसी जाड़े की बारिश से कोटकासिम के कुछ घर बह गए, जो कि सब-तहसील हैडक्वार्टर है । इसके बावजूद साहबी नदी नहीं बांधी गई है ।

16 Hrs.

दो साल पहले जो बड़ा भारी फ्लड आया था, उसमें कोटकासिम के विकास-खंड का दफ्तर और डिसपेंसरी आदि सब बह गए । साहबी नदी उस इलाके में इतना भय पैदा करती है कि वहां के लोग पुराने रिवाज के मुताबिक घाघरा और लुगड़ी वग़ैरह उसको अर्पण करते हैं । हमारे यहां कहावत है : "अकबर बांधी न बंधू, न रेवाड़ी जाऊं, कौट तले के नीचे से साहबी नाम कहाऊं" । इसका मतलब यह है कि बहुत पहले ही अकबर बादशाह ने इस नदी को बांधने की कोशिश की थी । वह चाहता था कि किसी प्रकार इसको रेवाड़ी ले जाया जाये । जैसा कि श्री गजराज सिंह राव ने कहा है, रेवाड़ी में पानी की बहुत कमी रहती है । वहां रेलवे विभाग के लिए पानी बावल के पास से जाता है जो पहले

नाभा स्टेट में था । रेवाड़ी में यह नदी नहीं गई । यह नदी राजस्थान में स्थित कोट-कासिम के नीचे से हो कर जाती है और साहबी नदी के नाम से मशहूर है । यह नदी यहां पर नजफ़गढ़ नाले में मिल जाती और वह नाला भर जाता है । उससे सारी दिल्ली घिर जाती है और नेशनल हाईवे नम्बर 8 टूट जाता है । उस समय साहबी नदी का ख़तरा महसूस होता है ।

मैं डा० राव से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हम को बिजली नहीं दे रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिये कोई पग नहीं उठा रहे हैं । उन्होंने रेडियो पर एलान किया था कि हम दिल्ली और जयपुर को रेवाड़ी होकर हाई टेन्शन लाइन से जोड़ देंगे । पहले तो वह हरियाणा से डरते थे, लेकिन अब तो हरियाणा की सरकार ख़त्म हो गई है । इसलिए अब वह इस साहबी नदी को जल्दी से जल्दी बांधें जिससे उनके पुराने वादे पूरे हों और जो काम अकबर बादशाह के ज़माने में नहीं हो सका, उसको भारत सरकार अब करे । डा० राव खुद एक टैक्निकल आदमी हैं । वह श्री कंवर सेन की तरह तजुर्बा रखते हैं । वह श्री कंवरसेन की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर साहबी नदी को बंधवायें और हमारी फ़ाइव-यीअर प्लान में जो अस्सी लाख रुपया रखा गया है, जो हर योजना में लेप्स हो जाता है, उसका उपयोग करें ।

श्री सरजू पांडेय (ग़ाज़ीपुर) : सभापति महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । अभी प्रस्तावक महोदय ने अपने इलाके की अवस्था का अच्छी तरह से वर्णन किया है । मुझे भी उस इलाके को देखने का सौभाग्य मिला है । उन्होंने ठीक कहा है कि वहां पर पानी के लिए झगड़े होते हैं, मारपीट होती है और कुंओं पर हज़ारों लोगों की कतार खड़ी मिलती है ।

मैं इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की एक बात कहना चाहता हूं । मंत्री महोदय को ख़ास तौर से ऐसे पिछड़े हुए इलाकों के लिए कोई न कोई योजना बनानी चाहिए, जहां लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है । उत्तर प्रदेश का बांदा ज़िला एक ऐसा क्षेत्र है, जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है और जहां आज भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । माननीय सदस्य ने हरियाणा के अपने क्षेत्र की जो दशा बताई है, वही दशा उत्तर प्रदेश की है । इसके अतिरिक्त और भी कई ज़िले हैं, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ़ नहीं है । मेरा सुझाव है कि देश के उन विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे किया जाये, चाहे वे किसी भी प्रदेश के हों, और उनके लिए ऐसी योजनायें तैयार की जायें, जिससे जनता को कुछ लाभ हो ।

आज स्थिति यह है कि सरकार के इंजी-नियर केवल इस दृष्टि से योजनायें बनाते हैं कि किस तरह से उनको ज्यादा कमीशन मिले । माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि पहले से यह तय हो जाता है कि अगर अमुक योजना को एप्रूव करा दो, तो तुम को एक कार मिल जायेगी । पांच, छः रुपये सैंकड़ा से लेकर सोलह रुपये सैंकड़ा तक उन लोगों के कमीशन बंधे हुए हैं । यह बात मेम्बर साहबान भी जानते हैं और मिनिस्टर साहब भी जानते हैं, लेकिन इन अफ़सरों के आगे उनकी कुछ नहीं चलती है ।

अगर मंत्री महोदय चाहें, तो वह इस बारे में पार्लियामेंट के सदस्यों की राय ले लें, हालांकि वह उनकी राय कभी नहीं लेते हैं; वह केवल नौकरशाही पर निर्भर हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके वह चौथी पंच-वर्षीय योजना में इस योजना को प्राथमिकता दें जिसके बिना जनता को बहुत परेशानी है ।

[श्री सरजू पाण्डेय]

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन साहब, साहबी नदी हरियाणा में, और खास तौर से अलवर, झज्जर, रोहतक और गुड़गांव में तबाही मचाती है । यह साहबी नदी नहीं, इस इलाके की मौत है । डा० राव हमारे इन्द्र देवता हैं। चूंकि हरियाणा की एसेम्बली टूट गई है, इसलिए अब यह पार्लियामेंट ही हरियाणा की एसेम्बली है और डा० राव ही हरियाणा के इर्रिगेशन मिनिस्टर हैं। एक बूढ़ा शेर और एक जवान वज़ीर, एक का दिमाग़ और दूसरे की ताकत, ये दोनों मिल कर हरियाणा की कायाकल्प कर दें । हमारे यहां तबाही हो रही है।

श्री राव गजराज सिंह ने अपने रेज़ोल्यूशन में सिर्फ़ रेवाड़ी और झज्जर का ज़िक्र किया है, लेकिन मैं सारे हरियाणा की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इस रेजोल्यूशन की पहली लाइनों में कहा गया है, "बैकवर्डनेस आफ़ हरियाणा"। हरियाणा में सिर्फ़ साहबी नदी ही खतरा नहीं है। वहां पर मारकंडा जैसे छोटे-छोटे दरिया बड़ी तबाही मचाते हैं। मारकंडा दरिया ने करनाल और रोहतक जिलों में तबाही मचा रखी है । मिनिस्टर साहब हरियाणा की चप्पा-चप्पा ज़मीन से वाकिफ़ हैं। मारकंडा दरिया की वजह से रोहतक शहर और ज़िला डूब गए थे और हर मकान में छः-छः फीट पानी भर गया था । वह ढांसा बांध पर भी तशरीफ़ ले गये थे । मिनिस्टर साहब उस इलाके से जितना प्यार रखते हैं, अगर वह उस प्यार के मुताबिक अमल भी करते तो हमारी कायाकल्प हो जाती ।

एक बार महाराजा रणजीत सिंह हाथी पर बैठ कर कहीं जा रहे थे । एक बुढ़िया लोहे का तसला लेकर आई और कहने लगी, "राजा, इस तसले को सोने का बना दो।" महाराजा ने कहा, "यह बावली बुढ़िया है। मेरे छूने से यह तसला सोने का कैसे बन जायेगा "? बुढ़िया ने कहा, "इस तसले को हाथ लगा दो, तुम्हारे हाथ लगाते ही यह सोने का बन जायेगा "। महाराजा ने उस तसले को हाथ लगाया और सोचा कि इस बुढ़िया ने पते की बात कही है । उसने हुकम दिया कि उस बुढ़िया को उस तसले के वज़न का सोना दे दिया जाये ।

मिनिस्टर साहब हमारे लिए महाराजा रणजीत सिंह हैं, इन्द्र देवता हैं। वह कई दफ़ा रोहतक में जा चुके हैं। हरियाणा में जो वैस्टर्न जमना कैनाल है, उसको उन्होंने खुद देखा है । उन्होंने उस नहर की पटरी पर सौ मील तक गाड़ी चलाई है और वह सारा इलाका देखा है । हमारा दो-तिहाई इलाका सेम ने मार दिया है । हमारा बेहतरीन इलाका है, जो लायलपुर और अच्छे से अच्छे मैदानों को मात कर सकता है । जितना पंजाब का इलाका है, उतना ही हरियाणा का इलाका है, पंजाब का एरिया 18,032 स्क्वैयर माइल्ज़ है और हरियाणा का 16,835 स्क्वैयर माइल्ज़ । लेकिन पंजाब में 65 परसेंट ज़मीन में आबपाशी होती है और हमारे यहां कुल 30 परसेंट। जब हम लोग पंजाब में थे, तो हमारे साथ ठीक सलूक नहीं हुआ । लेकिन अब मिनिस्टर साहब एक तो हमारे यहां की सेम, वाटरलागिंग, का इलाज करें और दूसरे, मारकंडा और घग्घर को नाथ डालें, उनके सींग पकड़ें, क्योंकि ये दरिया हमारे यहां बहुत तबाही मचा रहे हैं । इसके अलावा ओखला के नज़दीक जमुना से नहर निकालने की जो पुरानी स्कीम है, उसको भी पूरा किया जाये। यह हमारी स्कीम बना दें। यू० पी० वाले मजबूत भाई हैं। यह हमारी बात पार पड़ने नहीं देते । हम तो इनका मुकाबिला कर नहीं सकते । बड़े हैं, वैसे भी इनसे झुकते हैं। एक तो गुड़गांव जिले को खराब करने वाली ओखला से नहर निकली है, उसको बनवा दें । दूसरे हमें इस मारकंडा से

साहिबी से और बच्चर से बचाएं। एक हमारी नहर ठीक करा दें । मेरे हल्के में हजारों आदमियों ने नारे लगाए थे जब आप मौके पर गए थे और आपने वादा भी किया था। तो उस इलाके के लिए आप कोई व्यवस्था जरूर करें । यह झज्झर तहसील जो है और हरियाणा का यह इलाका जो है इसके लिए कहावत मशहूर है कि आठ फिरंगी नौ गोरे, इनको मार भगाएं हरयाणा के चार छोरे। यह वह इलाका है । आपके लिए जान देने वाला इलाका है । जय जवान जय किसान वाला इलाका है । तीस-तीस हजार फुट की बुलन्दी पर हमारे हरयाणे के छोरे बैठे हैं। हरयाणे की बटालियन ने अकेले चीनियों को नीचे आने नहीं दिया । यह तो वह बेहतरीन छोरे हैं। हम देश के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करना चाहते हैं। यह हमारी जरूरत है । लेकिन हम इस बात का एहसास करते हैं कि हमारी जमीन पानी से मरी पड़ी है । यहां पानी है ही नहीं । कोरी रेत है। पैसा लगा कर आप हमें पानी दे दें और सारे देश को हम खिलाएंगे। सही बात है । मैं सही बात कहता हूं । मेरे भाई ने अलवर की बात की । अलवर, झज्झर, रिवाड़ी, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और हिसार का सारा इलाका सूखा पड़ा है जबकि सोना उगलने वाली यह सारी जमीन है । आप थोड़ी सी कृपा कर दें । पानी का इन्तजाम कर दें। और यह मौका है 6 महीने का। आप के हाथ में सब कुछ है । हरयाणा की सारी बेहतरी का दारोमदार आपके हाथ में है।

राव साहब का में खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा । उन्होंने हरयाणे के ऊपर खास ऐहसान किया जो यह रेजोल्यूशन ले आये । और चेयरमैन साहब, आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : मैं राव साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि उसका हिस्सा साहिबी का और बच्चर का हमारे यहां भी पड़ता है । अभी बच्चर की बाढ़ से राजस्थान में इतना नुकसान हुआ कि दो साल पहले हजारों एकड़ जमीन पानी के अन्दर डूब गई और डूबी रही । भरतपुर का एरिया उसी बाढ़ के पानी से तीन महीने तक डूबा पड़ा रहा । आज भी लाइनों पर पानी खड़ा हुआ है और चारों तरफ समुद्र दिखाई पड़ता है । यह उसी बाढ़ के कारण है । मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस तरह का खिलवाड़ देश के साथ हो रहा है । कई सालों से इस सभा के अन्दर यह प्रस्ताव पास होते आ रहे हैं लेकिन वह वैसे ही पड़े रहते हैं। अभी जा करके इनसे कह दो कि फलां जगह उद्घाटन करना है तो खटाखट चार-चार मोटरें ले कर पहुंच जायेंगे और उद्घाटन कर आयेंगे । लेकिन वह पत्थर पड़ा रह जायगा । बांध नहीं बनेगा । इनको तो भाषण, चाटन और उद्घाटन चाहिए । मैं कहता हूं कि देश के साथ इस प्रकार धोखा करना और इस प्रकार की बातें करना बन्द होना चाहिये । अगर कोई योजना बनाई जाय तो अधूरी न छोड़ी जाय और अगर अधूरी छटती है तो कम-से-कम उस एण्ड पर उसे छोड़ें जहां से सिंचाई का काम चल सके । 4 लाख एकड़ जमीन के लिए अब तक इन्तजाम कर सके हैं जबकि 400 लाख एकड़ के लिए होना चाहिए । कितने शर्म की बात है ? इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस बांध को बनाया जाय । उसका पानी राजस्थान की तरफ जायेगा तो अच्छा उत्पादन होगा । उससे देश आबाद होगा और पी० एल० 480 का तो नाम मत लो । सारे हिन्दुस्तान भर में इसकी ओट में जो आप चुनाव का शिकार खेलते हो, वह हमें मालूम है । इसलिए यह पी० एल० 480 बन्द कर दो और इसके जरिये एलेक्शन का जो धन्धा है वह भी बन्द करो ताकि अपोजीशन को भी कुछ मौका मिले।

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बांध को बनाया जाय ।

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : Mr. Chairman, Sir, you may ask me why I am interested in this Resolution. By destiny or by fate, I have been allotted land in Haryana. I have been given land in a village which is named after the Kaurvas though I am very fond of Pandvas, that is, Kaurvakhurd which is in Naraingarh tahsil in the district of Ambala. Therefore, I have some interest in Haryana. At the same time, I must say that Shri Gajraj Singh Rao is my un-official teacher.

SHRI GAJRAJ SINGH RAO : This is wrong; I am his student.

SHRI D. C. SHARMA : He has always taught me something about the problems that face Haryana; he has always told me all about the history of Haryana and, I think, I am receiving his instructions very devotedly and I am grateful to him for that.

I think, we should not widen the scope of this. That is my first point. Ghaghar is there and that affects my village. Markanda is there and it influences me when I have to go from this place to Chandigarh or some other place. But I do not want that we should cast our net very wide. I want that we should stick, first of all, to Sahibinadi. Sahibinadi, I am told, is called as such because it is the river of prosperity. But, unfortunately, it has belied its name. Instead of bringing prosperity to the *ilaka*, it has brought destruction. It has brought destruction in Rohtak, as my hon. friend just now said; it has brought destruction sometime in Delhi also which was responsible for a lot of loss of life and a loss of cattle and other things. This is a phenomenon which occurs almost every year.

Now, the country to which I belong and to which all of us belong has specialised in river projects. If I go abroad and people ask me, "What have you done ? What are you doing ?", I tell them that we have built up some river projects of all kinds, big, medium and small. The river project to which Shri Gajraj Singh Rao has referred will be called, I think, a small project. It will not cost very much money; it will not involve a lot of expenditure; it will not involve any kind of uprooting of all people as some other projects have done; it will not involve any migration of the people from one territory to other territory. It is a river project which, I should say, is acceptable on all counts. At the same time, this river project is going to save Delhi, Rohtak and other cities. Therefore, I think, this project should be given first priority in the Fourth Five Year Plan.

My second point is this. My hon. friend referred to the problem of drinking water. I have been to Rewari sometimes and I have found there that the problem of drinking water is very very difficult. Anyone who gives you sweet drinking water becomes your real uncle because you get mostly salted water there.

Thirdly, this project has been blessed by very eminent engineers. Our Minister is also an Engineer and he has now become eminent because he is a Minister. Before he became a Minister, he was also an eminent Engineer. Therefore, he is doubly eminent, eminent as an Engineer and eminent as a Minister. This project has been blessed by Rai Bahadur Kanwar Sen, I met him in Bangkok and asked him, "Why have you come here?" he said "They want me here." He is known all over the world. The Indus Water Treaty is also something in which he had some hand. Then it has been blessed by Mr. H. L. Uppal, who also knows a lot about this problem and who is in charge of some irrigation research station. It has also been blessed by the Planning Commission. Now what is the difficulty ? The difficulty is this that our Government, a very fine Government—I am a small part of that Government—takes too long to decide a thing, it takes too long a time to take decisions. The difficulty is this. He says, slow and steady wins the race. We should remember that we are now in the jet age; we are not living in the age of tortoises. There may be some persons who may take their inspiration from a tortoise, but I take inspiration from the supersonic jet.

This scheme should be accepted by the hon. Minister. That is number one. Number two is that it should be executed. Let us give that scheme to the people of Haryana as a gift; whatever you may call it, you may give it as a gift because Haryana is a land of farmers; it is also a land of great warriors. Let the warriors and the peasants of

Haryana feel the glow of freedom by having this.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : सभापति महोदय, डा० के० एल० राव साहब जैसे काबिल मंत्री के सामने में समझता था कि शायद कोई ऐसा प्रस्ताव आयेगा जो आज के जमाने के हिसाब से गहरी खेती करने लायक इस देश को पानी जुटाने का काम कर सके। लेकिन अफसोस यह है कि आज के बीज, आज का खाद, आज की तकनीक उन सब का फायदा इस देश के एक फीसदी आदमी उठाते हैं। सैंकड़ों साल पहले जब बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तब अंग्रेज़ों ने कभी यह तय किया था कि अकाल न पड़ सके, इस के लिये नहरें खोदी जांय और इतना पानी किसानों को दिया जाय कि वे अकाल से बच जांय। यह एक प्रकार से सुरक्षात्मक सिंचाई नीति थी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, सभापति महोदय, कि इतने दिन अंग्रेज रह गये और 20 साल हमें आजाद हुए हो गये, गहरी खेती करने के लिये भरपूर पानी देने का काम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अंग्रेजों की नीति, जिसमें सुरक्षात्मक ढंग से पानी मिल सके, अकाल न पड़े, अभी उसी नीति को पूरा करने में शायद कांग्रेस सरकार और बहुत से साल लगाना चाहती है। इस ज़माने में अगर किसी गांव में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो या कहीं अकाल का सवाल पैदा हो, तो सीधे-सीधे हिसाब लगाया जाता है कि क्या इस देश में उतना पानी उपलब्ध नहीं है? श्रीमन्, इस देश में पानी ज़मीन के अन्दर भी है और ज़मीन के ऊपर भी है, वर्षा से भी आता है, जिसे हम बन्द के ज़रिये रोक सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी उस दिशा में नहीं सोचा।

मंत्री जी इंजीनियर रहे हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन इंजीनियर रहने और योग्य बनने से काम नहीं बनता—काम बनता है पैसे से। जब मंत्री जी के पास पैसा ही नहीं है तो इनकी योग्यता धरी रह जायगी और धरी रह गई अब तक। पैसा कहां से आयेगा—जब तक इस सरकार की नीति इस प्रकार की नहीं होगी कि इस देश को खेती के लिये भरपूर सिंचाई का इन्तज़ाम करना है—तब तक पैसा नहीं आयेगा। इसलिये मैं सारी ज़िम्मेदारी मंत्री जी पर नहीं डालना चाहता हूं, बल्कि मैं मंत्री जी के द्वारा इनके मंत्री मंडल का ध्यान खींचना चाहता हूं। दिये तले अन्धेरा—दिल्ली में बैठे हो, बराबर में राजस्थान और हरियाणा है जहां एक दम सूखा पड़ा हुआ है। ये वह लोग हैं, जिनके यहां अगर दूध पैदा होता है, तो आपके यहां चले आते हैं—लो बाबू जी, दूध पी लो और जब वह कहते हैं कि भैंस के लिये बरसीम चाहिये, बरसीम जब पैदा होगी जब सिंचाई का इन्तज़ाम होगा, सिंचाई जब होगी जब उसके लिये पानी का इन्तज़ाम हो, उनको बिजली दी जाय—लेकिन इसके लिये आपके पास पैसा नहीं रहता है। फिर आप कहते हैं कि दिल्ली की नुक्ताचीनी करना चाहते हो—मैं दिल्ली की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता—दिल्ली भी इसी देश का एक भाग है। लेकिन अफसोस होता है जब एक काबिल आदमी के होते हुए हम सही तरीके की नीति को निर्धारित नहीं कर सकें।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हरियाणा और राजस्थान देश के ऐसे इलाके हैं जो कपास का भण्डार पैदा कर सकते हैं। उनसे कपास पैदा न करवा कर, आज हम अमरीका से उधार कपास लाते हैं या मिश्र से कपास खरीदने के लिये जाते हैं। ये वह इलाके हैं जो तिलहन का भण्डार पैदा कर सकते हैं, सरसों से लेकर मूंगफली तक पैदा कर सकते हैं, उनसे यह चीजें पैदा न कराकर सूरजमुखी का तेल रूस से और सोयाबीन का तेल अमरीका से मंगाते हैं इसको देख कर अफसोस होता है।

इतने बड़े काबिल आदमी के यहां पर होते हुए, मैं यह आशा करता था कि आपके ज़माने में गहरी खेती करने के लिये भरपूर सिंचाई वाली बात चलेगी, लेकिन अफसोस यह है कि अभी तक सुरक्षात्मक सिंचाई की नीति सरकार

[श्री महाराज सिंह भारती]

की चल रही है और वह भी अभी तक देश में पूरी नहीं हो पाई है। इसलिये यह तो एक बहुत छोटा-सा मासूम प्रस्ताव है, ऐसे ऐसे हजारों प्रस्ताव यहां पर आने चाहियें, तब जा कर केवल अकाल को दूर करने वाली बात होगी, उत्पादन बढ़ने वाली बात तो अलग रही।

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : I thank Rao Gajraj Singh and other hon. Members for participating in this discussion. I wish to state without any hesitation that this is one of the projects on which the Ministry of Irrigation & Power is set to construct it at the earliest. The Sahibi Nadi is a very small river, in fact a very small river—I wish very often it is a much bigger river. It is also very erratic, the rainfall in this region from which the river comes is sometimes as low as 8" and sometimes it goes upto 40" so that the flow in the river varies greatly, very much from year to year. But in these years in which it comes in large quantity it is causing a lot of trouble both for Haryana and Delhi. Therefore, realising the importance of controlling this river from the point of floods and also from the point of control of alkalinity in the Haryana areas, we have drawn up schemes. In the beginning there was some trouble for want of agreement between Haryana Government, Rajasthan Government and Delhi in the sharing of the cost of this project. But I am glad to say that a few weeks back I had called a meeting of the Ministers of Haryana and Rajasthan and the Chief Executive Counciller of the Delhi State and we arrived at an agreement that the cost of the project will be divided equally between flood control and irrigation. The flood control cost will be borne equally by Delhi and Haryana. The irrigation cost will be borne between Haryana and Rajasthan in the ratio of 60:40 as Haryana is to get more benefits of this project. The project is estimated to cost Rs. 2·5 crores. We have asked the Rajasthan Government to draw up the scheme and finalise it. The Haryana Government has been asked to prepare the scheme for the countour-bunding of the various tributaries of Sahibi Nadi so that the water may be used for flushing out the alkalinity in the soil. Therefore, we have asked both of them to draw up the schemes and as soon as they are received, they will be further processed and the project will be undertaken.

I once again say this is a very medium type of project, the cost to be shared between three parties—the Rajasthan, Haryana and Delhi. Therefore, it should not be difficult for the parties to find money. Also, this work will take about two to three years and, therefore, it shall not be very much of a burden on the States to financially support these projects.

I am, therefore, very glad to accept the resolution moved by Shri Gajraj Singh Rao, and I would say that it will be our endeavour to see that this project is carried out as quickly as possible.

श्री गजराज सिंह राव : चेयरमैन साहब, मैं तमाम हाउस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने 110 साल के बाद हम लोगों की ग़दर की सज़ा माफ़ कर दी है। अब वे लोग प्रासपरस होंगे। दिल्ली और दूसरे सब इलाकों को सब्ज़ी और दूध देने की हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर इस स्कीम के पूरा होने के बाद मैं दस गुना पैदावार न दे दूं, तो आप मुझे सज़ा दें।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"This House is of opinion that, with a view to provide irrigation and drinking water facilities to backward areas of Haryana (Rewari and JhajjarTehsils) and Alwar District of Rajasthan and in order to avoid constant flooding of Najafgarh area of Delhi State and damage to railway line (metre gauge), the implementation of Sahibinadi scheme (raising bunds etc.) is of urgent necessity and importance and urges upon the Government its speedy completion and effective utilisation".

The Resolution was adopted.

16·32½ HRS.

RESOLUTION RE. WAGE BOARD FOR BIDI INDUSTRY.